मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सपरिवार डीग स्थित श्रीनाथजी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर से गोवर्धन पर्वत की लगभग 21 किलोमीटर की सप्तकोसीय परिक्रमा पूरी की। मुख्यमंत्री ने अन्य श्रद्धालुओं की तरह 'पांच दंडवती' (साष्टांग प्रणाम) लगाकर सप्तकोसीय परिक्रमा प्रारंभ की। इस दौरान उन्होंने मुखारविंद, मानसी गंगा एवं दानघाटी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना की। परिक्रमा के दौरान स्थानीय नागरिकों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया।

अजिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार, राजेश यादव अतिरिक्त मुख्य सचिव बने

राज्य सरकार ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 61 आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति की

आईएएस अजिताभ शर्मा

आईएएस आलोक गुप्ता

आईएएस दिनेश कुमार

आईएएस राजेश कुमार यादव

जयपुर, 31 दिसंबर (कासं)। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के 1996 बैच के चार वरिष्ठ अधिकारी, अजिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, दिनेश कुमार और राजेश कुमार यादव को राज्य सरकार ने पदोन्नति देकर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया है। उन्हें "अबोव सुपरटाइम वेतन श्रृंखला" से मुख्य सचिव वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर को आदेश जारी कर राजस्थान के 61 आई.ए.एस. अधिकारियों को पदोन्नति दी है।

इसी प्रकार वर्ष 2001 बैच के आई.ए.एस. नवीन जैन और कृष्णकांत पाठक (केके पाठक) को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है। इन्हें सुपर टाइम से अबोव सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2010 बैच के 11 आईएएस को चयन वेतन श्रृंखला से सुपरटाइम वेतन श्रृंखला में प्रमोशन दिया गया है। इनमें जयपुर कलेक्टर जितेन्द्र सोनी, प्रकाश राजपुरोहित, इंद्रजीत सिंह, नेहा गिरी, विश्व मोहन शर्मा, कन्हैयालाल स्वामी, नलिनी कठोतिया, राजेन्द्र विजय, शक्ति सिंह राठौड़, प्रज्ञा केवलरमानी और महावीर प्रसाद शामिल है।

इसी तरह वर्ष 2013 के बैच के 22 आईएएस अफसरों को आईएएस की जूनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में प्रमोट किया गया है। इनमें आशीष गुप्ता, नथमल डिडेल, नम्रता वृष्णि, कानाराम, अंशदीप, आलोक रंजन,

आईएएस के के पाठक

आईएएस नवीन जैन

निकया गोहाएन, अरविंद कुमार पोसवाल, प्रदीप के. गवांडे, महावीर प्रसाद मीणा, खजान सिंह, डॉ. रश्मि शर्मा, लक्ष्मी नारायण मंत्री, इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल, डॉ. मनीषा अरोड़ा, पुष्पा सत्यानी, पुखराज सेन, श्रुति भारद्वाज, अरुण कुमार पुरोहित, मुकुल शर्मा और अजय सिंह राठौड़ शामिल है।

इसी तरह वर्ष 2017 बैच के 10 आई.ए.एस. अधिकारियों को आईएएस की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला (लैवल 12) में पदोन्नत किया है। इनमें उत्सव कौशल, डॉ. गौरव सैनी, श्वेता चौहान, अवधेश मीणा, देवेन्द्र कुमार, सुशील कुमार, अक्षय गोदारा, श्रीनिधि बी.टी, डॉ. सौम्या झा और डॉ. महेन्द्र खड़गावत शामिल है।

इसी प्रकार वर्ष 2022 बैच के 12 आई.ए.एस. अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी गई है। इनमें यक्ष चौधरी, प्रीतम कुमार, यशार्थ शेखर, डॉ. अंशु प्रिया, सक्षम गोयल, दिव्यांश सिंह, श्रद्धा गोमे, मोहित कासनिया, भैसारे शुभम अशोक, सोनिका कुमारी, श्रेष्ठा श्री और चारू शामिल है।

राज्य सरकार ने इसी आदेश में 7 अधिकारियों को पदोन्नत करके यथावत कार्यभार भी सौंपा है। आदेश के मुताबिक, अजिताभ शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, दिनेश कुमार को अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय, जन अभियोग, निराकरण, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग का जिम्मा सौंपा है। इसी प्रकार राजेश कुमार यादव को महानिदेशक, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है।

इसी तरह नवीन जैन को प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, संपदा, स्टेट मोटर गैराज एवं नागरिक उड्डयन विभाग एवं पदेन चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एवं महानिदेशक, नागरिक उड्डयन राजस्थान जयपुर एवं आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का जिम्मा सौंपा है। नथमल डिडेल को वित्त (कर) विभाग में विशिष्ट शासन सचिव लगाया है। वहीं, अरविंद पोसवाल को मुख्यमंत्री का विशिष्ट सचिव बनाया है, वे पूर्व में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। इकबाल खान को आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, नि:शक्तजन राजस्थान का कार्यभार सौंपा है।

- **राज्य के 2010 बैच के आईएएस अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल में प्रमोशन मिला है। इसी तरह 2013 बैच के 22 आईएएस अधिकारियों को सलैक्शन स्केल दिया गया है और 2017 बैच के 10 आईएएस अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी गई। वर्ष 2022 बैच के आईएएस अधिकारियों को वरिष्ठ श्रृंखला में प्रमोशन दिया।**

भारत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि भारत में इस घटक (साल्ट) का प्रयोग सामान्य रूप से दर्द और बुखार में होता है। इसके उच्च खुराक के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

यह सलाह स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उन चिंताओं के बाद आयी, जिनमें रोगियों में लीवर को नुकसान पहुंचने की आशंका जतायी गयी थी। चिंताओं में चेतावनी दी गयी थी कि कुछ मामलों में यह घातक हो सकती है। भारतीय औषधि नियामक (सीडीएससीओ) ने भी केंद्र के फैसले का समर्थन किया है।

यह निर्णय हमारे देश में गिद्धों की घटती आबादी को लेकर पर्यावरणीय चिंताओं से पैदा हुआ। पैनल ने चेतावनी दी कि निमेसुलाइड गिद्धों के लिए खतरनाक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त रूप से पक्षियों की आबादी में ड्रग की सुरक्षा रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया। रिपोर्टों से पता चला कि जिन गिद्धों को निमेसुलाइड दी गयी, वे दवा देने के 24 घंटे के भीतर मर गये।

राजकीय सम्मान के साथ खालिदा ज़िया का अंतिम संस्कार

विदेश मंत्री जयशंकर ने रहमान को प्र.मंत्री मोदी का संवेदना पत्र दिया

ढाका, 31 दिसंबर। बंगलादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रहीं बेगम खालिदा जिया को बुधवार को प्रशंसकों एवं समर्थकों की भारी भीड़ के बीच शाम करीब 4:30 बजे सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष एवं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित संसद भवन में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के निकट दफनाया गया। इस दुख की बेला पर हजारों लोगों ने उनके लिए दुआ की। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और बैतुल मुकर्रम मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मलेक ने 3:02 बजे

- **बेगम ज़िया की सुपुर्द-ए-ख़ाक रस्म म कुछ ही लोगों को मौजूद रहने की इजाज़त दी गई थी। भारत तथा एशिया के कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधि खालिदा ज़िया की अंतिम यात्रा में मौजूद थे।**

माणिक मिया एवेन्यू पर जनाजे की नमाज पढ़ायी। बेगम जिया के दफन में शामिल होने की कुछ चुनिन्दा लोगों को ही इजाजत थी। इसमें उनके परिवार के सदस्य, वरिष्ठ राज्य अधिकारी, सरकारी अधिकारी, विदेशी मेहमान, राजनयिक और बीएनपी के वरिष्ठ राजनेता मौजूद थे। उनके दफन में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, चुनिंदा बीएनपी नेता, अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री के आखिरी सफर में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्रतिनिधि और अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इससे पहले जयशंकर ने बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान से निजी रूप से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पत्र सौंपा।

अजित पवार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिक सीटों पर चुनाव लडने की संभावना है। इस सूची में मलिक परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं - मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड नंबर 165 से, उनकी बहन डॉ. सईदा मलिक वार्ड नंबर 168 से और भतीजी बुशरा मलिक वार्ड नंबर 170 से चुनाव लडेंगी। मलिक परिवार कुर्ला-अणुशक्ति नगर क्षेत्र में प्रभावी है।

उल्लेखनीय है कि मलिक को 23 फरवरी 2022 को एन्फोर्समेन्ट डायरेक्ट्रेट (ईडी) ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी पाकिस्तान स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 के सीरियल बम विस्फोटों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहीम की गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्डरिंग जांच से संबंधित थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक पर कुर्ला दाऊद इब्राहीम की गवाला बिल्डिंग की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था।

संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी सरदार शाह वली खान, जो 1993 के बम धमाके मामले में सजा काट रहा है, और सलीम पटेल, जो दाऊद इब्राहीम की स्व. बहन हसीना पार्कर का प्रतिनिधि था, के नाम थी। ईडी का मामला एनआईए द्वारा दाऊद इब्राहीम-मनी लाउंड्रिंग मामले में दर्ज एफआईआर के बाद आया था। 11 अगस्त 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को मैडिकल ग्राउण्ड पर जमानत दे दी थी, और तीन दिन बाद, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।

इंदौर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दूषित पानी पीने से 12लोगों की मौत के मामले में हाई कोर्ट में बुधवार को जनहित याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट प्रशासन से मांगी है।

जहरीले पानी के मामले में जनहित याचिका वकील रितेश इनानी ने दायर की है। एक अन्य याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी ने दायर की है। एडवोकेट द्वारा दायर याचिका में इसमें दोषी अफसर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी की जान के साथ अफसरों ने लापरवाही की। मामले के दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से इस मामले की 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एडवोकेट इनानी ने बताया कि कोर्ट ने पीड़ितों का निशुल्क इलाज करने के निर्देश भी दिए हैं।

दिल्ली ने सबसं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डिग्री से ज्यादा की गिरावट देखी गयी। इस वजह से मौसम विभाग ने बुधवार के लिए 'कोल्ड डे' की चेतावनी जारी की।

दिनभर आसमान में घने बादल छाये रहे और धूप नहीं निकलने से ठंड और ज्यादा महसूस की गयी। ठंडी हवाओं ने सुबह से ही लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में यह ठंड बढ़ी है।

सेवाकाल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सेवा की गणना भी उसी दिन से होनी चाहिए थी। राज्य सरकार की मनमानी से उसे सेवा परिलाभ देरी से दिए गए और इस कारण वह अपने साथी शिक्षकों से पिछड़ गई। इसलिए उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही सेवा काल की गणना करते हुए समस्त परिलाभ दिए जाएं। मामले की सुनवाई करते हुए हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को समस्त सेवा परिलाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर अदा करे।

'ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता पर चीन का दावा भारत के साथ मज़ाक'

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बाद अब चीन दावा कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल हुए सैन्य कार्रवाई में उसकी मध्यस्थता से अचानक ऑपरेशन सिन्दूर रोका गया था। पार्टी ने इसे भारत के साथ मजाक करार दिया और कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सरकार ने जो कुछ बताया, ये दावे उसके विपरीत है और इस तरह के दावे देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को चीन के दावों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि

- **कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए जवाब देना चाहिए**

राष्ट्रपति ट्रम्प पहले ही बार-बार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर आयात शुल्क का डर दिखाकर दोनों देशों (भारत-पाकिस्तान) के बीच संघर्ष को रुकवाया था और अब चीन भी दावा कर रहा है और इस पर मोदी की चुप्पी बेहद परेशान करने वाली है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बारे में चार जुलाई को उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा, "ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था। चूंकि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीन के दावे चिंताजनक हैं और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वे देश की जनता को दी गई जानकारी के उलट हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मज़ाक बनाते प्रतीत होते हैं।" कांग्रेस नेता ने कहा, "इस दावे को चीन के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने चीन से बातचीत शुरु कर दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बातचीत चीन के शर्तों पर हो रही है।

'यूक्रेन, रूस का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और क्षेत्र बढ़ना चाहिए और रूस खुद को साम्राज्य मानता है।" यह चेतावनी क्रेमलिन की बढ़ती विद्रोही बयानबाजी के बीच आई है। अपने वार्षिक टेलीविजन प्रश्नोत्तर सत्र में, पुतिन ने आगे सैन्य कार्रवाई से इनकार करने से मना कर दिया और कहा कि बीबीसी रूस केवल तभी तनाव को बढ़ने से रोकेगा, यदि पश्चिम "सम्मान" दिखाए और मॉस्को के हितों को स्वीकार करे। उन्होंने फिर से नाटो के पूर्वी विस्तार को एक विवाद का कारण बताया और पश्चिमी शक्तियों पर धोखाधड़ी और उकसावे का आरोप लगाया। पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर भी दोष मढ़ते हुए कहा कि उन्होंने "यह स्थिति खुद बनाई है" और जानबूझकर रूस के साथ युद्ध के डर को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले के बयान में, उन्होंने यूरोपीय संघ के नेताओं को अवसरवादी बताते हुए कहा कि वे रूस के पतन से लाभ उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। शांति वार्ताओं के ठप्प होने, सैन्य योजनाओं के तेज़ी से लागू होने और परमाणु-संभावित तनावों के बीच, बुडानोव का मूल्यांकन एक गंभीर संभावना को उजागर करता है कि यूक्रेन अंततः खेल का अंत नहीं हो सकता, बल्कि एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत भी हो सकता है, जो दुनिया को 1945 के बाद के सबसे खतरनाक युद्ध में खींच सकता है।

सरकार ने वोडाफोन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समर्थन, नए पूंजी निवेश और परिचालन प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर हैं।

कुछ हिस्सेदारों को उम्मीद थी कि कैबिनेट एजीआर कर्ज का एक हिस्सा या पूरी राशि माफ कर सकती है। इसके बजाय, सरकार ने मोरेटोरियम का विकल्प चुना, जो कंपनी को अपने संचालन को स्थिर करने के लिए समय देने वाला कदम माना जा रहा है

सूत्रों के अनुसार, फ्रीज़ किए गए कर्ज का पुनर्मूल्यांकन एक समिति द्वारा ऑडिट रिपोर्ट्स के आधार पर किया जाएगा और समिति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के फैसले सरकार के हितों की रक्षा के उद्देश्य से थे, खासकर क्योंकि अब सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ये उपाय भी कर्ज की व्यवस्थित वसूली, दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और कंपनी के लगभग 20 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उठाए गए थे।

वोडाफोन आइडिया को बचाने का निर्णय यह दिखाता है कि सत्ता में बैठी सरकार बड़े उद्योग और व्यापार की तरफ भारी झुकी हुई है, जबकि बेरोज़गारी, ग्रामीण संकट और बढ़ती कीमतों से जूझ रहे आम लोगों के प्रति इसकी पक्षपाती नीति आज के फैसले से साफ दिखाई देती है।

ममता बजर्नी विधानसभा चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **अब ममता जी ने दीघा के समुद्र तट पर विशाल जगन्नाथ मंदिर बनाया है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के समान। वे नये आधुनिक, नये शहर, न्यू टाउन में भी "दुर्गांगन" का निर्माण करा रही हैं। दीघा स्थित नए जगन्नाथ मंदिर का संचालन उन्होंने इस्कॉन को सौंप दिया है।**
- **क्या ममता बनर्जी दो घोड़ों, हिंदू व मुसलमान वोट बैंक, पर एक साथ सवारी करने का असंभव काम कर पाएंगी या धरातल पर गिर जाएंगी इस प्रयास में। अब तक वे अपनी राजनीतिक चतुराई से अपना हर लक्ष्य प्राप्त करती आई हैं। पर, इस बार शायद कुछ बड़ा ही ग्रास मुंह में रख लिया है, जिसे चबाना बहुत कठिन लग रहा है।**

दरअसल ममता की रणनीति का एक मुख्य आधार ही कांग्रेस को तोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करना था, क्योंकि वे खुद भी कभी कांग्रेस में थीं और युवा नेता के रूप में उन्हें राजीव गांधी का विशेष समर्थन मिला था। ये राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने उन्हें पहली बार विदेश यात्रा पर भेजा था, जिसका जिक्र वे बाद में करती रहीं।

लेकिन जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई तो उन्होंने अपने मातृ संगठन से अलग होकर, कांग्रेस को तोड़कर, अपना संगठन खड़ा किया। अब, जबकि कांग्रेस लगभग मिट चुकी है, तो ममता ने कांग्रेस के वोट बैंक को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, खासकर मुसलमानों के बीच।

इस रणनीति के तहत, ममता ने कई बार हदें पार कर दीं। कांग्रेस को हराने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वाम दलों, खासकर सीपीआई (एम), के मुस्लिम समर्थकों को अपने पाले में लाने की थी, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी रहीं।

उनके कई अग्रिम पंक्ति के लड़ाके सीपीआई (एम) से आए हुए लोग थे, वे टूटकर आए थे, लेकिन बाद में वही लोग उनके लिए बोझ बन गए और उन्हें उनसे दूरी बनानी पड़ी। मुसलमानों को अपनी पार्टी में बड़ी संख्या में लाने के बाद अब उन्हें उतना फायदा नहीं मिल रहा, जितना पहले मिल रहा था।

उनके अधीन कई मुस्लिम नेता ममता की उम्मीद से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं और कुछ तो बगावती मूड में भी हैं। यह साफ नहीं है कि यह उनके खिलाफ असली विद्रोह है या सिर्फ दिखावा, लेकिन अब मुसलमान भी केवल छोटे-मोटे लाभों से संतुष्ट रहने के बजाय अपने राजनीतिक फायदे खुद तय करना चाहते हैं।

उनके ही एक बड़े और मजबूत नेता हुमायूं कबीर अब बहुत बड़े हो गए है और उन्होंने ममता को सीधी चुनौती दे दी है। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है और मुसलमानों की निष्ठा अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। उनका आकलन है कि जब उनकी पार्टी मुस्लिम वोट खींच लेगी, तब वे राज्य में किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा दल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा।

हालांकि यह अभी शुरुआती दिन हैं और यह साफ नहीं है कि मुस्लिम वोट अलग-अलग दलों के बीच किस तरह बंटेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा फिर से कांग्रेस और सीपीआई (एम) की ओर लौटेगा, जबकि कुछ का मानना है कि कई छोटे मुस्लिम दल इन वोटों को अपनी ओर खींच लेंगे।

इन बदलते हालात को देखते हुए ममता बनर्जी अब अपना दायरा बढ़ाने और पश्चिम बंगाल की मुख्यधारा के वोट बैंक, यानी बंगाली हिंदुओं की ओर फिर से लौटने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू वोटरों का समर्थन पाने के लिए ममता खुलेआम हिंदू मतदाताओं को रिझाने वाले कदम उठा रही हैं। ममता ने पहले ही दीघा में, जो ओडिशा सीमा के पास बंगाल का प्रसिद्ध समुद्री तट है, एक भव्य जगन्नाथ मंदिर बनवाया है। इस मंदिर की संरचना काफी हद तक पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जैसी है।

तथापि, कोई भी यह नहीं मानता कि यह मंदिर पुरी के मूल मंदिर की बराबरी कर सकता है। ममता ने दीघा के इस मंदिर का प्रबंधन इस्कॉन को सौंप दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, आगे भी वो बहुत कुछ कर रही हैं।

कल ही उन्होंने राज्य के पॉश न्यू टाउन इलाके में "दुर्गांगन" परियोजना का शिलान्यास किया। बंगाल में दुर्गा से जुड़ी हर चीज का गहरा भावनात्मक असर होता है और अब उन्होंने हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए दुर्गा मंदिर और पार्क की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है।

लेकिन यह कार्यक्रम कई तरह के विवाद में फंस गया है। दुर्गा मंदिर के लिए चुनी गई जमीन को मुसलमानों की जमीन बताया गया और मुसलमानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद अदालत ने निर्माण पर रोक लगा दी और आनन-फानन में मंदिर स्थल बदलना पड़ा।

निश्चित रूप से यही उनकी चुनावी रणनीति का अंत नहीं हो सकता। वे इस समय दो नावों पर सवार हैं, जो लगभग असंभव काम है। लेकिन उनका राजनीतिक कौशल दूसरे सभी खिलाड़ियों की मिली-जुली संपूर्ण काबिलियत से कहीं ज्यादा है।

संघ की मदद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आलोचकों और विश्लेषकों द्वारा इस अपील को, विशेषकर जनसांख्यिकी एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर, भाजपा-आरएसएस के वैचारिक नैरेटिव के साथ जुड़ने का प्रयास माना जा रहा है। नायडू की पार्टी, टीडीपी औपचारिक रूप से भाजपा के संगठनात्मक ढांचे से बाहर भले ही है, लेकिन नायडू के ये कदम और उनका असर आसानी से अनदेखे नहीं किये जा सकते।

दिल्ली में भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस उभरते समीकरण को भागवत और नायडू के बीच एक "संतुलन साधने का प्रयास" बताया है, और कहा कि दोनों पक्ष आंतरिक अस्थिरता के बीच संवाद बनाए रखने में रुचि रखते हैं। विभिन्न सूत्रों के अनुसार, भाजपा के उच्च नेतृत्व के कुछ हिस्से हाल के संगठनात्मक निर्णयों से नाखुश हैं, विशेष रूप से एक अपेक्षाकृत अल्पज्ञात नितिन नबीन, जो बिहार के 45 वर्षीय विधायक हैं, को बिना व्यापक परामर्श के पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले के बारे में आरएसएस को भी अंतिम समय में ही सूचित किया गया था, जब निर्णय लिया जा चुका था। इन घटनाक्रमों ने भाजपा के भीतर नेतृत्व के उत्तराधिकार को लेकर असंतोष की चर्चा को हवा दी है।

पार्टी की आगे की राह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराधिकारी के सवाल पर चुपचाप बहस चल रही है। नायडू का नाम अब, कम से कम एक काल्पनिक विकल्प के रूप में, अनौपचारिक चर्चाओं में उभरने लगा है।

नायडू के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे भाजपा-आरएसएस पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे मंथन पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उनके एक साथी ने कहा, "सभी विकल्प खुले हैं" और बताया कि अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं, तो नायडू एक बड़ी राष्ट्रीय भूमिका निभाने से परहेज नहीं करेंगे। भाजपा के कुछ अंदरूनी सूत्र, सतर्कता के साथ, कहते हैं कि यदि पार्टी एक संक्रमणकालीन या आम सहमति वाले नेता की तलाश करती है, तो नायडू के नाम पर एक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में विचार किया जा सकता है, ताकि भाजपा को दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सके।

फिलहाल, यह सब केवल अनुमान हैं, न कि ठोस योजनाएं। फिर भी, राजनीति में, धारणाएं अक्सर वास्तविकता से पहले आती हैं। आरएसएस की ओर बढ़ रहे नायडू के कदमों, और भाजपा के आंतरिक असंतोष की वजह से आंध्र प्रदेश के नेता एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गए हैं, इस बार संघ से उनकी निकटता का असर आंध्र प्रदेश से कहीं आगे तक जाएगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908